भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2572

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

ब्लॉकचेन-आधारित भूमि अभिलेख

2572. डॉ. कडियम काव्यः

क्या ***ग्रामीण विकास*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि राजसहायता तक पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वारंगल में छोटे किसानों के लिए ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल भूमि रिकॉर्ड संबंधी योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तेलंगाना के लिए नियोजित पायलट परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में राजसहायता वितरण में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऐसी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण के साथ केन्द्रीय की क्षेत्र योजना के रूप में दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) को कार्यान्वित कर रहा है। वारांगल सहित देश में डीआईएलआरएमपी के तहत ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल भूमि अभिलेखों का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*****